

## प्रधानमंत्रीग्रामसड़कयोजना

25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया; 18 साल पहले स्थिति सक्रिय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) (IAST: प्रधान मंत्री ग्राम योजना) (हिंदी : , अंग्रेजी: प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना) भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

[1] ] मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले 178,000 (1.7 लाख) बस्तियों और 250 से अधिक आबादी वाले इलाकों में सभी मौसम सड़कों से जुड़े होने की योजना है 82% दिसंबर 2017 तक पहले से ही जुड़े हुए थे और शेष पर काम-की प्रगति मार्च 2019 (47 दिसंबर 2017) तक पूरा होने के लिए 47,000 बस्तियां चालू थीं। [2]

यह केंद्र प्रायोजित योजना [3] 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। [4] असम ट्रिब्यून ने बताया है कि इस योजना ने कई ग्रामीणों की जीवन शैली को बदलना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मणिपुर में नई सड़कों और कुछ अंतर-ग्राम मार्गों का उन्नयन हुआ है। [5]

## इतिहास

PMGSY ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकार में है और 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। [6] यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नवंबर 2015 के दौरान, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की घोषणा की गई थी कि इस परियोजना को केंद्र सरकार (60%) और राज्यों (40%) दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। )। 2000 में सरकार की घोषणा की गई थी।

लक्ष्य

इसका उद्देश्य सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना था

2003 तक 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी के साथ

2007 तक 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी के साथ

पहाड़ी राज्यों में, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों में जिनकी आबादी 500 और उससे अधिक है

२०० in तक २००० और उससे अधिक आबादी वाले पहाड़ी राज्यों, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों में। [a]

## **OMMAS**

इसे लागू करने के लिए, लक्ष्यों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली या OMMAS GIS प्रणाली विकसित की गई

थी। यह सी-डैक प्यून के ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक है। यह प्रणाली सड़क विकास के सभी चरणों को अपने प्रस्ताव मोड से सड़क पूर्ण होने तक प्रबंधित करती है और उनकी निगरानी करती है। प्रत्येक सड़क पर किए गए खर्च को ट्रैक करने के लिए OMMAS का अलग मॉड्यूल भी है। राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के आधार पर, ओएमएमएस विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है जो नागरिकों के अनुभाग (<http://omms.nic.in>) में देखने योग्य हैं। OMMAS में ई-भुगतान, पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइलें, इंटरएक्टिव रिपोर्ट आदि जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं [10]

## प्रगति

मैदानी इलाकों में 500 से अधिक और 250 से ऊपर की आबादी वाले 178,000 (1.7 लाख) बस्तियों को सभी मौसम सड़कों से जोड़ने की योजना है, 55% (97,838) मार्च 2014 तक जुड़े थे, 82% (80% या) PMGSY के तहत 131,000 या 1.3 लाख या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 2% या 14,620) दिसंबर 2017 तक जुड़े हुए थे। शेष 47,000 में से, 1700 को छोड़कर सभी पर काम चल रहा है, जो दिसंबर 2017 के अंत तक और 100% स्वीकृत किया जाएगा। कनेक्टिविटी मार्च 2019 (16 दिसंबर 2017 अपडेट) तक प्राप्त कर ली जाएगी। [2] लंबित कार्य में असम, जम्मू और

कश्मीर और उत्तराखंड के कठोर इलाके और साथ ही वामपंथी नक्सली-माओवादी अतिवाद राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ जिले और ओडिशा के मलकानगिरी जिले शामिल हैं। [२]

2004 से 2014 तक पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण की औसत गति 98.5 किलोमीटर प्रतिदिन थी, यह fy2016-17 में बढ़कर 130 किमी प्रतिदिन हो गई।

## **प्रभाव**

योजना ने कई ग्रामीणों की जीवनशैली को नई सड़कों और उन्नयन के साथ बदलना शुरू कर दिया है, जैसे मणिपुर में।

## **ग्रीनकवर**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम सड़कों के पास हरित आवरण को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह वृक्षों के पौधे रोपण के माध्यम से होता है जिसमें फल देने वाले वृक्षों के पौधे लगाना भी शामिल है। इन प्रयासों से सफलता के विभिन्न स्तर सामने आए हैं [

वेबसाइट [pmgsy.nic.in](http://pmgsy.nic.in)